भारतीय जनता पार्टी

(केंद्रीय कार्यालय)
11 अशोक रोड, नई दिल्ली–110001
दूरभाष : 233005700; **फैक्स** : 23005787

दिनांक : 06 जुलाई, 2009

लोकसभा में प्रतिपक्ष की उप–नेता श्रीमती सुषमा स्वराज द्वारा केन्द्रीय बजट 2009–10 के बारे में लोकसभा में दिया गया वक्तव्य

वित्तमंत्री श्री प्रणव मुखर्जी द्वारा प्रस्तुत केन्द्रीय बजट राष्ट्र के लिए निराशाजनक है। आर्थिक मंदी के दौर में सर्म्पूण देश बजट की एक ऐसे अवसर के रूप में प्रतिक्षा कर रहा था, जिससे अर्थव्यवस्था के अधोगमन को सुधारा जा सके। यह निष्प्रभ बजट स्पष्ट रूप में साबित करता है कि संप्रग सरकार नई उद्भावनाओं से शून्य है। संप्रग सरकार की समझ में नहीं आ रहा है कि विद्यमान स्थिति को किस प्रकार संवारा जा सके। यह केन्द्रीय बजट एक खोया हुआ अवसर बन गया है। आर्थिक सर्वेक्षण में सुझाए गए सुधारों से जो आशा की किरण दिखाई गई थी, वह क्षणिक बनकर रह गई। आर्थिक सर्वेक्षण में सरकार के अंदर बैठे अर्थशास्त्रियों द्वारा सरकार को सुझाया गया खाका संप्रग को स्वीकार्य नहीं हुआ।

राष्ट्र को ऐसे बजट की आशा थी, जिससे संवर्धित आर्थिक क्रिया–कलापों को बढ़ावा मिलता है, जिससे निवेश को बढ़ावा मिलता है, जिससे राजस्व घाटे को कम करने का दिशा–बोध प्राप्त होता है। इस बजट से रोजगार पैदा किए जाने की आशा थी। राष्ट्र को आशा थी कि कृषि क्षेत्र संकट से उबर पाएगा। बजट से आशा थी कि ढांचागत संरचना में भारी सार्वजनिक/निजी–निवेश से अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। हमारी पार्टी ने आशा की थी कि भारत के निर्यात में हो रहे ह्रास पर अंकुश लग जाएगा और वो अपनी पटरी पर लौट आएगा। कराधान कम करके उपभोक्ताओं की जेब में अधिक धन आएगा। राष्ट्र को ब्याज दरों में कमी हो जाने का लाभ मिलेगा। ऐसा सोचना तर्कपूर्ण था कि इससे स्थायी संपदा और आवासीय क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा। खेद है कि वित्तमंत्री के मन में उपर्युक्त में से किसी भी विषय को प्राथमिकता देने की बात नहीं आई।

यह बजट देश में विस्तृत आर्थिक कार्य–कलाप सृजित करने अथवा निवेश आकर्षित करने में पूरी तरह अक्षम है। बजट में स्वीकार किया गया है कि राजकोषीय घाटा 2.7 प्रतिशत से बढ़कर 6.8 प्रतिशत हो गया है। यह चिंताजनक आंकड़ा भी सत्य को पूरी तरह उजागर नहीं करता है। राज्यों के आर्थिक घाटे के साथ–साथ बजट से इतर मदे इस आंकड़े को दोगुना कर देंगी। सकल घरेलू उत्पाद में 4.8 प्रतिशत का राजस्व घाटा और अधिक चिंता का मामला है।

अपने पहले के कार्यकाल में संप्रग ने वादा किया था कि वह प्रतिवर्ष 1 करोड़ और अधिक रोजगार पैदा करेगा। 2004–09 की अवधी के दौरान 5 करोड़ अतिरिक्त रोजगार पैदा करने की बजाय भारत में रोजगारों की कमी दिखाई दी है। आर्थिक सर्वेक्षण में इस बात

को आंशिक रूप से स्वीकार किया गया है। वित्तमंत्री ने बजट में रोजगार बढ़ाने के लिए कदम उठाने की घोषणा करने के बजाय ऐसी पवित्र आशा व्यक्त की है की सरकार प्रतिवर्ष 1.2 करोड़ रोजगार पैदा करेगी, जो संप्रग – II के कार्यकाल में कुल रोजगार बढ़कर 6 करोड़ हो जाएंगे। संप्रग – I के दौरान बुनियादी ढांचे के विकास को भारी आघात लगा था। इस बजट में सार्वजनिक निवेश अथवा राजकोषीय उपायों से ऐसा कोई सार्थक संकेत नहीं मिलता है कि इस दौरान ढांचागत सुविधाओं के लिए निवेश में वृद्धि होगी। ऐसी कोई रियायत भी नहीं दी गई है, न ही कोई नया विचार प्रस्तुत किया गया है, जो घटते निर्यात की प्रवृत्ति को उलटने में सक्षम हो। आशा थी कि वित्तमंत्री की तरफ से आवासीय और अचल संपत्ति के क्षेत्र को कुछ न कुछ प्रोत्साहन दिए जाएंगे। वित्तमंत्री ने यथावत स्थिति बनाए रखना ठीक समझा। कराधान के आधार में वृद्धि के चलते करो में रियायत की आशा की गई थी ताकि उपभोक्ता की क्रय शक्ति में इजाफा हो सके। अप्रत्यक्ष करो में 2000 करोड़ रूपए की वृद्धि हो गई है। करदाताओं पर यह भी एक बोझ होगा। बजट में किसी भी रूप में किसानों की गरीबी को ध्यान में नहीं रखा गया है। किसानों के लिए 7 प्रतिशत की ब्याज दर उन्हें तंगहाल बनाए रखेगी। गत सत्र में राष्ट्रपति जी के भाषण ने झूठी आशा जताई थी कि विनिवेश पुनः प्रारंभ होगा। देश में विनिवेश वातावरण के अभाव में ऐसी संभावना प्रतीत नहीं होती है कि कोई सार्थक विनिवेश किया जा सकता है। विनिवेश के लाभों को महसूस करते हुए चाहे वे अल्पसंख्यकों के हित में क्यों न हो बजट में 1120 करोड़ रूपए का मामूली सा लक्ष्य रखा गया है। बढ़ते हुए राजकोषीय घाटे को देखते हुए यह समुद्र में एक बूंद के समान होगा।

प्रधानमंत्री ने देश को आश्वस्त किया था कि जो काला धन इस समय टैक्स हैवनों (Tax Havens) में छिपाकर रखा गया है, उसको देश में वापस लाने के लिए पक्के कदम उठाए जाएंगे। वित्तमंत्री ने इस दिशा में कोई कदम उठाने के लिए बजट के अवसर का उपयोग नहीं किया है।

किंतु भाजपा सशस्त्र सेनाओं में वन–रैंक–वन–पेंशन की शुरूआत का स्वागत करती है। बदनाम फ्रिंज बैनिफिट टैक्स कॉमेडिटीज़ ट्रांजेक्शन टैक्स समाप्त कर दिए गए है। जब से ये टैक्स लगाए गए है तब से ही भाजपा की इन्हें समाप्त करने की लगातार मांग हो रही थी।

(श्याम जाजू)
मुख्यालय प्रभारी